महत्वपूर्ण एवं खास

कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने आठ प्रकरणों में स्वीकृत की आर्थिक सहायता राशि

सारंगढ़.बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने आरबीसी 6.4 के तहत विभिन्न कारणों से मृत्यु हो जाने पर कुल आठ प्रकरणों में मृतकों के निकटतम परिजनों को 4.4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की भटगांव तहसील के ग्राम सेंदूरस निवासी जयपाल सिंह 55 वर्ष की मृत्यु जुलाई 2022 को तालाब के पानी में डूबने से हो गई। मृतक की पत्नीध्आवेदिका सुषमा सिंह को आरबीसी 6.4 के अंतर्गत संबंधित तहसीलदार से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। इसी ग्राम के कृष्णा कुमार की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी रूखमणी यादव कोए भटगांव तहसील के ही ग्राम मनपसार के मदनलाल साहू की मृत्यु तालाब में डूबने से हो गई। उनकी पत्नी महेश्वरी साहू कोए ग्राम मधुवनकला ,तहसील भटगांव के भागवत मनहर की मृत्यु सांप के काटने से हो जाने पर उनकी पत्नी करमा बाई कोए 4.4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति जिला प्रशासन द्वारा प्रदाय की गई है। इसी प्रकार बिलाईगढ़ तहसील के ग्राम अलीकुद ;तालगांवद्ध निवासी विजय कुमार पटेल की मृत्यु करंट लगने से हो जाने पर उनके पिता बजरंग पटेल कोए ग्राम पचरी निवासी दिनेश कुमार की सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी प्रेमबाई कोए सारंगढ़ तहसील के ग्राम घोराघाटी निवासी चम्पाबाई बरिहा की मृत्यु आग में जलने से हो जाने पर उनके पति बंशीलाल बरिहा को तथा बरमकेला तहसील अंतर्गत ग्राम झनकपुर की कौशल्या पटेल की मृत्यु सर्पदंश से हो जाने के कारण उनके पुत्र सेतकुमार पटेल को आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। इन सभी प्रकरणों में आरबीसी 6.4 में विहित प्रावधानों के तहत मृतकों के निकटतम वारिसों को 4.4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है।

चालू खरीफ सीजन में 11.58 लाख किसानों को 4961 करोड़ का कृषि ऋण वितरित

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश के किसानों को चालू खरीफ सीजन 2023 के लिए सहकारी बैंकों द्वारा बिना ब्याज के अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराई जा रही है। चालू खरीफ सीजन में अब तक प्रदेश के 11 लाख 58 हजार 669 किसानों को 4961 करोड़ 27 लाख रूपए का कृषि ऋण वितरित किया जा चुका है, जो कि लक्ष्य का 81 प्रतिशत है। विगत खरीफ सीजन में इसी अवधि पर 3928 करोड़ 71 लाख का ऋण वितरण किया गया था। इस तरह गत वर्ष की तुलना में चालू खरीफ में 1032 करोड़ 56 लाख रूपए अधिक का ऋण वितरित किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश की 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में 6100 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उद्यानिकी फसलों के लिए ब्याज मुक्त कृषि ऋण का प्रावधान किया गया है। सहकारी बैंकों के माध्यम से उद्यानिकी फसलों के लिए 230 करोड़ रूपए का लक्ष्य रखा गया है। निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 16.34 करोड़ रूपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। अपेक्स बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से धान के अलावा उद्यानिकी की अधिसूचित फसल जैसे बैगन, टमाटर, अदरक, मिर्च, फूलगोभी, आलू, पपीता, अमरूद, केला, करेला, लौकी, परवल, कद्दू, बरबट्टी, तरोई, जिंमीकंद, शिमला मिर्च, गाजर, मूली, ककड़ी, खीरा, लहसून, हल्दी आदि फसलों के ऋणमान निर्धारित किया गया है। सहकारी समितियों की कृषि ऋण साख व्यवस्था को अधिक गतिशील बनाने के लिए अपेक्स बैंक द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के जिला नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगद एवं कृषि आदान सामग्रियों के वितरण की सतत रूप से मानिटरिंग करें एवं किसानों की खेतीगत आवश्यकताओं की पूर्ति त्वरित गति से की जाए।

छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य, हमें केन्द्र से मिले ज्यादा से ज्यादा मदद - मुख्यमंत्री

❒ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रायपुर में 7600 करोड़ रूपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास

❒ परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ किया

रायपुर (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, एनसीसी ग्राउंड में आयोजित समारोह में 7600 से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास और शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है, इसलिए छत्तीसगढ़ को ज्यादा से ज्यादा मदद केन्द्र से मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर आये हैं। प्रभु श्रीराम के ननिहाल और माता कौशल्या की भूमि में मैं उनका स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री जी से हम अनेक मंचों में मिलते हैं और नीति आयोग आदि की बैठकों में मिलते हैं। हम मांगे भी करते हैं लेकिन उन्हें और दोहराना नहीं चाहता। मैं गडकरी जी के साथ भी बैठता हूँ जितना मांगते हैं उससे ज्यादा ही देते हैं।

मुख्यमंत्री ने इसके पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हेलीपेड पहुंचने पर उनकी अगवानी की तथा समारोह के मंच पर उन्हें राजकीय गमछा पहनाकर और मिलेट्स से बने उत्पाद भेंटकर उनका स्वागत किया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केन्द्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री रेणुका सिंह, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, लोकसभा सांसद अरूण साव और सुनील सोनी, विधायक डॉ. रमन सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

समारोह में 7600 करोड़ की लागत की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ- समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 7600 करोड़ रूपए की लागत की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ किया। उन्होंने इनमें से राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित लगभग 6,400 करोड़ रूपए की लागत की पांच परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिन दो परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, उनमें जबलपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के रायपुर-कोडेबोड़ खंड की 988 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित 33 कि.मी. लंबी 4 लेन वाली सडक़ और एनएच-130 के बिलासपुर-अंबिकापुर खंड के 1261 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित 53 किलोमीटर लंबे बिलासपुर-पथरापाली खंड पर निर्मित 4-लेन की सडक़ का लोकार्पण शामिल है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 6-लेन वाले ग्रीनफील्ड रायपुर-विशाखापत्तनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें - एनएच-130 सीडी पर 1368 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले 43 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले झांकी-सरगी खंड एनएच-130 सीडी पर 1471 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले 57 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले सरगी-बसनवाही खंड और एनएच-130 सीडी पर 1307 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले 25 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले बसनवाही-मारंगपुरी खंड का विकास शामिल है। 2.8 किलोमीटर लंबी 6-लेन सुरंग इसका एक प्रमुख घटक है - उदंती वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में वन्यजीवों के आसान आवागमन के लिए 27 रास्ते और 17 बंदर छतरियों का निर्माण भी किया जाएगा।

इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने 750 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित 103 किलोमीटर लंबी रायपुर-खरियार रोड रेल लाइन के दोहरीकरण, 290 करोड़ रूपए की लागत से विकसित केवटी-अंतागढ़ को जोडऩे वाली 17 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन का लोकार्पण किया और हरी झंडी दिखाकर अंतागढ़ से रायपुर नई ट्रेन को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कोरबा में 130 करोड़ रुपये से अधिक लागत से निर्मित 1700 सिलेण्डर दैनिक क्षमता के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण तथा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को 75 लाख कार्डों के वितरण का शुभारंभ किया।

5 सूत्रीय माँगों को लेकर कर्मचारियों ने किया सरकारी काम बंद

❒ मंत्रालय-संचालनालय-न्यायालय- मैदानी कार्यालय हुआ बंद- कमल वर्मा

❒ काम बंद हड़ताल से सरकारी दफ्तरों के ताला बंद- संयुक्त मोर्चा

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के आव्हान पर अपने 5 सूत्रीय माँगों के लिए कर्मचारियों ने प्रदेश के सरकारी कामकाज को ठप्प कर दिया।

सरकार द्वारा कर्मचारियों के असल मुद्दों को नजरअंदाज करने का आक्रोश सभी जिलों में दिखाई दिया। मंत्रालय, संचालनालय, न्यायालय सहित प्रदेश भर के शासकीय कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा ।प्रदेश भर के जिला, ब्लॉक/तहसील मुख्यालय में कर्मचारियों ने धरना, प्रदर्शन एवम् रैली निकालकर स्थानीय प्रशासन को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा,महासंघ के संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालयीन संघ के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राजपूत ने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते निर्णय नहीं लिया तो 1 अगस्त से 23 से अनिश्चितकालीन हड़ताल होना तय है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कर्मचारियों को केन्द्र के समान सातवे वेतनमान में गृहभाड़ा भत्ता देना होगा। गौरतलब है कि अभी कर्मचारियों को छटवे वेतनमान में गृहभाड़ा भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से महँगाई भत्ता देने में सरकार आनाकानी कर रही है। सरकार ने पिंगुआ कमेटी का गठन किया लेकिन कर्मचारी संवर्गो का वेतन विसंगति निराकरण जैसे मुद्दों का समाधान आज पर्यन्त नहीं हुआ। जन घोषणा पत्र में अनियमित/संविदा/ दैनिक वेतन भोगी/कार्यभारित/अन्य कर्मचारियों के नियमितीकरण का उल्लेख है।जोकि नहीं हुआ। वहीं चार स्तरीय वेतनमान के मामले में भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू जरूर कर दिया। लेकिन पेंशन हेतु प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना नहीं होने से योजना का व्यापक लाभ नहीं मिलेगा। तकनीकी पेंच के कारण शिक्षक (रुक्च) संवर्ग सहित अन्य कर्मचारियों को पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। पेंशन हेतु अहर्तादायी सेवा को 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष करने के माँग पर सरकार ने निर्णय नहीं लिया। जिसके कारण कर्मचारियों का आक्रोश काम बंद हड़ताल में दिखा है।

इलेक्ट्रिक बसों का इंतजार हुआ लंबा, तीसरी बार टेंडर जारी करने की तैयारी

रायपुर (आरएनएस)। शहर की सडक़ों पर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का लोग उम्मीद लगाए हैं। इधर, नगर निगम डेढ़ वर्ष से अधिक समय से केवल सपने ही दिखा रहा है। नगर निगम के जिम्मेदारों को बसों के संचालन के लिए अब तक एजेंसी ही नहीं मिल पाई है। एजेंसी तय करने के लिए निगम की ओर से दो बार टेंडर जारी किया जा चुका है, लेकिन किसी कंपनी ने रूचि नहीं दिखाई। अब समयावधि समाप्त होने के बाद तीसरी बार टेंडर जारी करने की तैयारी की जा रही है।

विगत माह मई में एमआइसी सदस्य और नगर निगम के ट्रांसपोर्ट सेल के अध्यक्ष अजीत कुकरेजा ने महापौर एजाज ढेबर से मुलाकात कर बताया था कि चंडीगढ़ की तर्ज पर 50 बसों का संचालन करने की तैयारी है। पहले चरण में 12 करोड़ रुपये के खर्च से 10 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी, जो जून में संचालित होगी। दूसरे चरण में 40 बसों की खरीदी होगी, जिसके बाद पेट्रोल या डीजल पर चलने वाली बसों को सडक़ से हटा दिया जाएगा। उन्होंने अगस्त तक 50 बसों के संचालन का दावा किया था। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में एजेंसियां रूचि क्यों नहीं दिखा रही हैं, इसपर जल्द ही बैठक लेकर समीक्षा की जाएगी।

इलेक्ट्रिक बसों के शुरू होने से राजधानी के बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगेगा। साथ ही डीजल पर खर्च होने वाले भारी भरकम राशि की बचत होगी। बसें पूरी तरह से बिजली से चलेंगी, जिससे शोर तथा प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। लोगों को भी शांतिपूर्ण माहौल में यात्रा करने मिलेगी।

महिला ने अपने पुत्र-पुत्री के साथ मिलकर की पड़ोसी की हत्या

सूरजपुर (आरएनएस)। सूरजपुर मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर स्थित महेशपुर गांव में एक महिला ने अपने बेटे व बेटी के साथ मिलकर पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी। मृतक द्वारा महिला के चरित्र पर लांछन लगाने को लेकर महिला ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं आरोपी बेटा अभी भी फरार बताया जा रहा है किसकी तलाश की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार सूरजपुर मुख्यालय से लगे गांव महेशपुर में मृतक सुखलाल खेती किसानी का काम करता था। घटना के दिन मृतक पड़ोस में रहने वाली रनिया के घर गया हुआ था। इसी दौरान उसने रनिया के चरित्र को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद नाराज रनिया ने पड़ोसी के साथ मारपीट की। पड़ोसी ने घर लौट कर अपने बच्चों को अपनी आपबीती बताई, जब पडो़सी के बच्चे रनिया से मामले की जानकारी के लिए उसके घर पहुंचे तब रनिया और उसके बेटे तथा बेटी ने मिलकर पड़ोसी के बच्चों की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद सुखलाल की बेटी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी तभी फोन पर उन्हे सूचना मिली कि रनिया उसकी बेटी और बेटे ने मिलकर उसके पिता सुखलाल की हत्या कर दी है। मौके पर सुखलाल के बच्चो ने देखा कि सुखलाल के गले में लोहे की रॉड घुसी हुई थी और उसकी मौत हो चुकी थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक की बेटी के शिकायत के बाद रनिया और उसके बेटा बेटी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया वहीं बेटा फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है।

राहुल के समर्थन में धरने पर बैठे भूपेश, कांग्रेस के सभी कार्यक्रम रद्द

रायपुर (आरएनएस)। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं दी। कोर्ट ने 2 साल की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया। जिसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता सभी कार्यक्रमों को रद्द करके राहुल के समर्थन में धरने पर बैठ गए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कांग्रेसी नेताओं ने अंबेडकर चौक पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अंग्रेज केवल महात्मा गांधी से डरते थे भाजपा राहुल गांधी से डर रही है। अंग्रेज और भाजपा दोनों फूट डालो राज करो की नीति पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग डरे हुए हैं। सच का सामना नहीं कर सकते, राहुल गांधी सच की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं। अब तो लोकसभा से भी सदस्यता समाप्त हो गई है, फिर भी ये डर रहे है। राहुल गांधी ने भारत जोडऩे का काम किया। उन्होंने सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ी। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक हर जगह राहुल गांधी के साथ लोग थे। आज देश भर में सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी हैं। कश्मीर में सबसे प्रिय नेता राहुल गांधी हैं। कश्मीर में फोर्स ने रोका फिर भी नहीं रुके। राहुल गांधी को भाजपा कितना भी परेशान कर लें राहुल गांधी न झुकेंगे और न रुकेंगे।

उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से कांग्रेस न तो सहमत है और न ही संतुष्ट है। देश में न्याय प्रणाली के तहत जो रास्ते हैं वो अपनाएंगे।

मुख्यमंत्री बघेल आज बूथ चलो अभियान के तहत सामुदायिक भवन भाठागांव, रंग मंदिर बैजनाथ पारा और वृंदावन हॉल के कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। इसके अलावा टीएस सिंहदेव और मोहन मरकाम भी कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे लेकिन सभी कार्यक्रम रद्द करके धरना प्रदर्शन किया गया।

खड़ी ट्रेलर से टकराई यात्री बस, तीन लोगों की हुई मौत

बिलासपुर (आरएनएस)। अंबिकापुर नेशनल हाइवे पर तेज रफ्तार लक्जरी बस सडक़ किनारे खड़ी ट्रेलर से टकरा गई है। हादसा इतना भीषण था कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और तीन लोगों की मौत हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार रतनपुर थाना क्षेत्र के बेलतरा के पास सुबह 5 बजे के आसपास सडक़ किनारे खड़ी ट्रेलर से बस की टक्कर हो गई।जिससे बस में सवार 3 लोगो मौके पर ही मौत हो गई, वही 12 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है की बस में कुल 47 लोग सवार थे। जिसे अन्य राहगीरों ने डायल 112 को सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रतनपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तत्कालित उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। वही गंभीर रूप से घायलों को बिलासपुर अपोलो में भर्ती कराया गया है। बस अंबिकापुर विश्रामपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर जा रहे थी। तभी सुबह 5 बजे के आसपास ड्राइवर को झपकी आ गई और बस सडक़ किनारे खड़ी ट्रेलर से जा भिड़ी, फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच आगे की कार्रवाई में जुट गई।

मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रूपए की सहायता राशि की घोषणा- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अम्बिकापुर से आ रही बस के बिलासपुर के समीप दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मृत्यु पर गहरा दु:ख प्रकट किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि हम सब दु:ख की इस घड़ी में इन परिवारों के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों की आत्मा की शांति और उनके परिवारजनों को संबल प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बघेल ने इस दुर्घटना में घायल लोगों के समुचित इलाज के निर्देश प्रशासन के अधिकारियों को दिए हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.सी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

खरीफ फसल की सुरक्षा के लिए इस वर्ष भी प्रदेश में चलाया जाएगा रोका-छेका अभियान

रायपुर (आरएनएस)। राज्य में खुले में चराई कर रहे पशुओं के नियंत्रण और उनसे खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए इस वर्ष भी रोका-छेका का अभियान शुरू किया जा रहा है। रोका-छेका छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपरा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर इसे अभियान के रूप में राज्य में शुरू किया गया है, जिसके बड़े ही उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में चालू वर्ष के दौरान यह अभियान पुन: चलाया जा रहा है। इस संबंध में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय से कृषि विभाग ने सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को गांवों में 17 जुलाई तक स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप रोका-छेका अभियान चलाने के दिशा-निर्देश आज जारी कर दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ फसल बुआई कार्य के पूर्व खुले में चराई कर रहे पशुओं के नियंत्रण के लिए 'रोका छेका' प्रथा प्रचलित है, जिसमें फसल बुआई को बढ़ावा देने तथा पशुओं के चरने से फसल को होने वाली हानि से बचाने के लिये पशुपालक तथा ग्रामवासियों द्वारा पशुओं को बांधकर रखने पहटिया (चरवाहा) की व्यवस्था इत्यादि कार्य किया जाता है। इस प्रयास से न सिर्फ किसान जल्दी बुआई का काम कर पाते हैं, बल्कि दूसरी फसल लेने हेतु भी प्रेरित होते हैं।

कृषि विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी रोका-छेका प्रथा के अनुसार व्यवस्था की सुनिश्चितता की जाए। इसके लिए ग्राम स्तर पर 17 जुलाई तक स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप रोका-छेका अभियान चलाकर सभा आयोजित की जाये। साथ ही सभी निर्मित गौठानों में 30 जुलाई से पहले चारागाह की स्थापना की जाए। जहां चारा उत्पादन हो। इन कार्यों के लिए स्थानीय प्रचार-प्रसार कर ग्रामीणजनों की सहभागिता सुनिश्चित के भी निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों को रोका-छेका अभियान के तहत ग्राम स्तर पर बैठकें आयोजित करने कहा गया है, जिसमें 'रोका छेका' प्रथा के अनुरूप पशुओं से फसल बचाव का निर्णय ग्राम सरपंच, पंच, जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों के द्वारा लिया जाएगा। फसल को चराई से बचाने हेतु पशुओं को गौठान में नियमित रूप से लाये जाने के संबध में प्रत्येक गौठान ग्राम में मुनादी कराने और गौठानों में पशु चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन के निर्देश भी दिए गए हैं।

जारी निर्देश में 'रोका छेका' प्रथा अंतर्गत गौठानों में पशुओं के प्रबंधन व रखरखाव की उचित व्यवस्था हेतु गौठान प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करने भी कहा गया है। ऐसे गौठान जो सक्रिय परिलक्षित नहीं हो रहे हों, वहाँ आवश्यकतानुसार प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से समिति में संशोधन कर सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पहटिया, चरवाहे की व्यवस्था से पशुओं का गौठानों में व्यवस्थापन सुनिश्चित करने कहा गया है।

कृषि विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि वर्षा के मौसम में गौठानों में पशुओं की सुरक्षा हेतु व्यापक प्रबंध किया जाये। वर्षा से जल भराव की समस्या दूर करने के लिये गौठानों में जल निकास की समुचित व्यवस्था की जाये तथा गौठान परिसर में पशुओं के बैठने के लिए कीचड़ आदि से मुक्त स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।